Throwing Newspapers and Magazines to Dustbins by the sorting office

400. SHRI RAHMAN KHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it has come to notice of Government that postal sorting office in Delhi and other places throw newspapers and magazines to dustbins;

(b) whether the vigilance officials are investigating such incidences; and

(c) what steps Government propose to take to stop such incidences?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No. Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) Instructions regarding adoption of adequate precautionary measures already exist.

Loss Suffered by DOT Due to Delay in the Supply of Equipment by an American Company

401. SHRI RAGHAVJI:
SHRI DILIP SINGH JUDEV:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "DOT, USA Firm Lock Horns" which appeared in the India Express, dated the 4th April, 1995 and if so, what are the details thereof;

(b) whether it is a fact that the USA Company, Hughes is reluctant to abide by the terms of the contract awarded to it by the Department of Telecommunications, and if so, what is the action being taken or proposed to be taken by Government against the firms; and

(c) whether it is also a fact that because of the dealy in the supply of equipment by Hughes Company, the DOT, has lost several customers for its "V-SAT Telecommunication services, and if so, what is the extent of loss suffered by Government in this respect?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) The captioned news item regarding supply of equipment by M/s Hughes Network Systems Inc. USA, appeared in the Indian Express dated 5-5-95.

(b) No Sir.

(c) No Sir.

नए एल पी जी कनेक्शन के लिए धरोहर राशि की वसूली।

402. श्री दिग्विजय सिंह:
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए एल पी जी कनेक्शन प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं/जनता से ली जाने वाली धरोहर राशि का उद्देश्य क्या है और सरकार इस धरोहर राशि का कैसे उपयोग करती है और 30 जून, 1995 तक सरकार के पास कुल धरोहर राशि कितनी है;

(ख) क्या जनता से ली जाने वाली इस धरोहर राशि पर दूरसंचार मंत्रालय की तरह ब्याज देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है या क्या सरकार ने इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करना चाहेगी, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त इतनी बड़ी धनराशि को अवरुद्ध करने का औचित्य क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) और (ग) तेल कंपनियों द्वारा ग्राहकों को उधार स्वरूप दिए एल पी जी उपकरण के प्रति प्रतिभूति के रूप में जमाराशि ली जाती है तथा उपकरण वापस करने पर इसे वापस दे दिया जाता है।

इस जमा राशि का उपयोग एल पी जी उपकरणों की पर्याप्त इन्वेन्ट्री को सदैव प्रयोग की स्थिति में कायम रखने के लिए किया जाता है ताकि ग्राहकों की जरूरत को पूरा किया जा सके। तेल कंपनियों द्वारा औसतन प्रति

ग्राहक 1.5 सिलिंडर उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए रखा जाता है।

30.6.95 की स्थिति के अनुसार तेल कंपनियों द्वारा एकत्रित जमाराशि करीब 1700 करोड़ रुपए थी।

(ख) : जी, नहीं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता

403. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा परिषद् में भारत को स्थायी सदस्य बनाये जाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयास हो रहे हैं;

(ख) किन-किन देशों ने इस पहल में भारत का साथ दिया है; और

(ग) वर्तमान समय में कौन-कौन से देश सुरक्षा परिषद् के सदस्य हैं तथा सदस्यता का निर्धारण किस प्रकार होता है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) भारत ने यह कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के रूप में अपने सेवाएं देने के लिए तैयार है। सरकार अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने हेतु सभी आवश्यक प्रयास कर रही है।

(ख) और (ग): इस समय अमरीका, यू०के०, फ्रांस, रूसी परिसंघ और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23(1) द्वारा स्थायी सदस्यता दी गई थी।

नए सदस्यों को सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करना होगा और संयुक्त राष्ट्र महासभा के दो तिहाई बहुमत से इसका अनुमोदन किया जाना होगा, तथा इसके लिए पांच स्थायी सदस्यों के सहमति मत की भी आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने "सुरक्षा परिषद् में औचित्य पूर्ण प्रतिनिधित्व और इसकी सदस्य संख्या में बढ़ोत्तरी के प्रश्न" पर एक मुक्त कार्यदल नियुक्त किया है। इस समय यह कार्यदल किसी देश विशेष की उम्मीदवारी पर विचार नहीं कर रहा है।

Scaling the Dried wells by ONGC at sibsagar

404. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pelased to state:

(a) whether it is a fact that in the district of Sibsagar ONGC did not take proper care to seal the dried wells by filling up the same with sand so as to save the land from seismic eruption and damage caused annually by floods etc.;

(b) whether Government are also aware that it is causing a serious concern in view of the downward turn of the river Brahmaputra towards South and it is situated in regions more prone to earthquake; and

(c) if so, what are the details thereof and what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (c) No, Sir. In ONGC, the dried wells are abandoned by sealing the wells properly following a standard procedure in compliance with the provisions of Oil Mines regulation, 1984. The procedure followed in abandoning dried wells ensures that the abandoned wells do not pose any problem even under influence of extraneous factors like flood etc.

Loss to forest wealth in hilly districts of U.P. by forest

405 SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the district-wise estimated loss to forest wealth in the hill districts of U.P. by forest fires in May-June 1995;